भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1952

उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023

सोमवार, 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

कार्यबल की कमी

1952 डॉ. एम.ी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन देशों की पहचान की है जहां कार्यबल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन देशों में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उन देशों को कार्यबल को प्रशिक्षण देने और आपूर्ति करने की कोई योजना है; और

(ग) क्या सरकार वापस भेजे गए लोगों को इस संबंध में प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) जी हां, एनएसडीसी- इंटरनेशनल ने एमएसडीई के तत्वावधान में निम्नलिखित 16 देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में कुशल कार्यबल की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया है। अनुमान है कि आगामी पांच वर्षों में विभिन्न देशों में 37 लाख कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की वैश्विक मांग होगी।

(ख) अभिज्ञात प्रमुख देशों में भारतीय मिशन कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए विदेशी सरकारों/संगठनों के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव- जी टू जी और बी टू बी तक इस मंत्रालय की पहुंच की धुरी हैं। इस तरह के नियोजनों के माध्यम से एमएसडीई का उद्देश्य भारत से द्विपक्षीय भागीदारों के लिए कुशल कार्यबल की गतिशीलता को सुगम बनाना है। एमएसडीई के तत्वावधान में एनएसडीसी ने भारतीय कुशल कार्यबल की विदेशों में पहुंच, प्रशिक्षकों का क्षमता-निर्माण, नियोजक सम्बद्धता, आदि की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ बिजनेस टू बिजनेस करारों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, चालू वित्त-वर्ष के लिए बजट घोषणा के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विभिन्न राज्यों में 30 कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ताकि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सके और एतदर्थ विदेश स्थित भारतीय मिशन गंतव्य देशों में नियोक्ताओं को जोड़ने की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने विदेश मंत्रालय (एमईए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ संयुक्त रूप से 15 नवंबर 2022 को दस देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय मिशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों के साथ प्रथम वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन में अपने जनसांख्यिकीय लाभ और जीवंत कौशल इकोसिस्टम का लाभ उठाकर भारत को विश्व के कौशल हब के रूप में स्थापित करने की भावी योजना पर चर्चा की गई।

(ग) एमएसडीई प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) जैसी विभिन्न कौशल पहलों के माध्यम से प्रत्यर्पित लोगों सहित युवाओं के कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के अवसर प्रदान कर रहा है।

****